LOK SABHA

Wednesday, April 16, 1975/Chaitra 26, 1897 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI S M BANERJEE: Sir, I had sent in a motion

MR SPEAKER I am not allowing this It has become a daily practice I am not allowing you to move this, nor will it come on record

SHRI S M BANERJEE ...*

MR SPEAKER Not a word of that will go on record You are speaking without my permission I am not allowing anything.

टेलीविजन समाचार विभाग की स्थापना

*648. श्री लालजी भाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर समाचार प्रसारण मे सुधार करने के विचार से प्रत्येक टेलीविजन केन्द्र मे टेलीविजन समाचार विभाग स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या कुछ अधिकारी इस संबंध में बी०बी०सी० लन्दन से प्रशिक्षण प्राप्त कर के हाल ही मे लौटे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन टेलीविजन केन्द्रों में टेलीविजन समाचार विभाग स्थापित किये जायेंगे तथा वे वहां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हा।

(ख) जी, हा।

(ग) वर्तमान टेलीविजन केन्द्रो अर्थात् दिल्ली, बम्बई, श्रीनगर और अमृतसर से टेलीविजन समाचारो तथा सामयिक मामलों सम्बन्धी विभाग स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं और उनकी वित्तीय दृष्टि से जांच हो रही है। नया ढांचा वित्तीय मंजूरी के उपरान्त वजूद मे आयेगा।

श्री लालजी भाई : मै आप के माध्यम से जानना चाहता हूं—कलकत्ता और मद्रास मे जो टेलीविजन केन्द्र हैं उन में समाचार विभाग खोले जायेंगे या नहीं ? ऐसा कोई प्रस्ताव आप के सामने है या नहीं, यदि है तो क्या उस पर विचार हो रहा है ?

यदि समाचार विभाग अलग-अलग खोले जायेंगे तो उन में कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर नियुक्त किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो सवाल पूछा है वह कुछ और है। यह सवाल उस मे से नहीं निकलता है।

श्री लालजी भाई : मैंने पूछा है कि इन चार टेलीविजन केन्द्रो में जो समाचार विभाग खोले जायेंगे उन में कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर नियुक्त किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो अभी भी समझ मे नहीं आया। अगर आप को कुछ पता हो तो बतला दीजिये।

SHRI S. M BANERJEE He wants to know how many persons are going to be employed in the agency?

अध्यक्ष महोदय : आप की मदद का उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिये। लेकिन जो बात

* Not recorded.

2—6 L.S.S./75

पूछी गई है वह इस प्रश्न में से कैसे निकलती है ?

श्री लालजी भाई : मैं पूछना चाहता हूं कि इन समाचार विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कितने प्रतिशत स्थान दिये जायेंगे ? जो नये समाचार विभाग बनाये जायेंगे उन में कितने-कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर नियुक्त किये जायेंग ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा प्रश्न पूछें, लेकिन जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, वह इस में कहां है । मिनिस्टर को आप के प्रश्नों के लिये तयार हो कर आना पड़ता है, लेकिन आप जो भी पूछें उस का ताल्लुक मेन-क्वश्चन से होना चाहिये ।

श्री लालजी भाई : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि चार टेलीविजन केन्द्रों में अलग-अलग समाचार विभाग खोलने का निर्णय लिया है । मैं पूछ रहा हूं कि इन विभागों में कितने व्यक्ति किन-किन पदों पर नियुक्त किये जायेंगे?

श्री धर्मवीर सिंह : मैंने बतलाया है कि इस पर विचार हो रहा है, वित्तीय दृष्टि से इस की जांच हो रही है । जब जांच हो जायगी तब नियुक्तियों के बारे में निर्णय लिया जायगा और तब ही इस के बारे में बतलाया जा सकता है ।

श्री लालजी भाई : जिन चार टेलीविजन केन्द्रों में समाचार विभाग खोलने जा रहें हैं, उन में समाचार सम्बन्धी शिक्षा के लिये क्या कुछ अधिकारियों को विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिये भेजने का कोई प्रस्ताव है ? यदि है, तो कब और कितने अधिकारियों को भेजा जायगा और किन किन-देशों में भजा जायगा ?

दूसरा प्रश्न---टेलीविज़न केन्द्रों के समाचार विभागों में काम करने वाले अधिकारियों के लिये किस-किस प्रकार की विशेष सुविधाये रखी गई हैं तथा उन को कौन कौन सी विशेष सुविधायें देने का विचार है ?

श्री धर्मवीर सिंह : प्रशिक्षण के लिये और बाहर भेजने की ज़रूरत होगी तो उन को भेजा जायगा ।

श्री लालजी भाई : अध्यक्ष जी, मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं आया । समाचार विभाग में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के समाचारों को कितने प्रतिशत स्थान दिया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : पहले वह कायम तो हो ले ।

श्री लालजी भाई : वह बन तो गया है, लेकिन इन जातियों के लिये कितने प्रतिशत समाचारों को स्थान दिया जायगा ?

MR. SPEAKER: Your Quesion says:

"if so, the names of Television Centres where the "Television News Department" will be set up and the time by which it is likely to start functioning there."

आप का यह सवाल इस में नहीं निकलता है

श्री भान सिंह भौरा : अमृतसर टेलीविजन केन्द्र जब खोला गया था तो इस लिये खोला गया था कि लाहौर का रेडियो स्टेशन जो प्रचार कर रहा था उस को काउन्टर-एक्ट किया जाय । क्या आप कोई ऐसा विचार करेंगे कि पंजाब के लिये एक अलग न्यूज़ एजेन्सी सेक्शन खोला जाय तो अमृतसर में हो या पंजाब में और किसी जगह पर हो, जहां से न्यूज़ इकठ्ठी हो कर वहां पर आ सकें ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : सब से पहले तो मैं यह साफ़ करना चाहता हूं कि अमृतसर का टी०वी० केन्द्र लाहौर के प्रोपेगण्डे को काउन्टर-एक्ट करने के लिये नहीं खोला गया था, वह जनता के लिये खोला गया था, पंजाब के लिये खोला गया था । जहां तक न्यूज़ कलैक्शन सिस्टम की बात है, जलन्धर का स्टूडिओ मुकम्मिल हो जाने के बाद उस को देखा जायगा । फिलहाल हम अमृतसर से एक न्यूज़-बुलेटिन ब्राडकास्ट कर रहे हैं ।

SHRI INDRAJIT GUPTA: May I know whether it has been brought to the notice of the minister that there is considerable discontent among the news telecasters of this department on the ground that their duties and responsibilities are not fixed on the basic of merit but done arbitrarily? If so, may I know whether there is any proposal to set up any kind of independent evaluation committee which will see that these things are remedied?

SHRI I. K. GUJRAL: I am not aware of any discontent in the TV station. It has not been brought to my notice. Who should be given what job as in every station and in any organisation primarily depends on the leadership of the Station Director. So far as evaluation of programmes is concerned, that is done from time to time so that overall toning up takes place and in that we do associate outsiders also. However. I am willing to consider what my hon. friend has suggested.

Opening of P.C.Os. at Block Headquarters in Maharashtra

*649. SHRI A. S. KASTURE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the P. & T. Department has accorded any priority to the opening of Public Call Offices at the Block Headquarters in Maharashtra since the declaration of Block Headquarters as category stations for the purpose of opening of P.C.Os.;

(b) if so, names of the Block Headquarters in Maharashtra where the P.C.Os. are not yet provided; and

(c) the reasons for not providing P.C.Os. at Block Headquarters and the likely date when P.C.Os. would be provided?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGANNATH PAHADIA): (a) Amongst places of administrative importance eligible for provision of public call offices, Block headquarters have been included in the policy guidelines for the 8th Five Year Plan. P.C.Os. can be opened in these places even on loss provided the expected revenue is at least 25% of the annual recurring expenditure in ordinary areas. In the case of backward and hilly areas the minimum expected revenue should be 15% and 10% respectively.

No inter-se priority has been given to the opening of P.C.Os. at such stations in Maharashtra or other States.

(b) In Maharashtra, out of 220 Block headquarters, there is only one Block headquarters at Sangrampur in Distt. Buldana where the P.C.O. is not yet provided.

(c) The P.C.O. at Sangrampur could not be provided as the proposal involved a loss beyond the prescribed limit of 85% of the annual recurring expenditure. It is learnt that the Gram Panchayat is willing to make good the loss and has also made a payment. Other formalities for executing a guarantee bond are being completed before taking up the work.

SHRI A. S. KASTURE: May I know how much time the department is likely to take to provide a P.C.O. at Sangrampur in Buldana District?

SHRI JAGANNATH PAHADIA: As soon as the formalities are completed, it will be provided.

SHRI A. S. KASTURE: May I know whether there are any complaints about the working of the P.C.Os. in Buldana District of Maharashtra?

SHRI JAGANNATH PAHADIA: We receive many complaints about many exchanges and P.C.Os. If he brings to our notice any particular complaint, I will examine it.

श्री भागीरथ भवर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि पांचवी योजना में विकास खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हम खोल रहे हैं और आवश्यक शर्तें पूरी करने पर खोले जायेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल महाराष्ट्र में ही ऐसा होगा या भारत के प्रत्येक प्रदेश के विकास खंडों के मुख्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था आप करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : केवल महाराष्ट्र का सवाल नहीं है । भारत सरकार देश के लिये